भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1512

(दिनांक 08.03.2021 को उत्तर देने के लिए)

प्रमुख समाचार प्रकाशनों से खबरों को अचानक हटाया जाना

1512. श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक साक्षात्कार में यह दावा किया है कि देश में 'अत्यधिक लोकतंत्र' होने के कारण भारत में सुधार लाया जाना कठिन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी प्रमुख समाचार प्रकाशनों से उक्त कथन से संबंधित रिपोर्टों को अचानक हटा दिया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कदम इस खबर को सेंसर करने के लिए इन प्रकाशनों को मंत्रालय की ओर से दिए गए किसी निदेश का हिस्सा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उनके द्वारा की गई टिप्पणी से सहमत है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध ऐसा बयान देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ङ): नीति आयोग ने सूचित किया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग ने 11 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित एक विशिष्ट लेख में लिखा है कि एक प्रश्न के जवाब में उनके उत्तर को जानबूझकर गलत तरीके से उद्धृत किया गया और तोड़ा-मरोड़ा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने की अपनी नीति के अनुसार, सरकार प्रेस के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती है।

****